

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर**

अपील संख्या - 50/20

GCMS NO 2020/00088

कल्याण पुत्र रतन जाति कहार निवासी बरखेडा पुल करौली तहसील व जिला करौली  
अपीलांट

बनाम

1. विष्णु चंद पुत्र कल्याण प्रसाद जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली
2. मुंशी पुत्र परसादी जाति माली निवासी बरखेडा के पास करौली तहसील व जिला करौली(मृतक)
  - 2/1. महेश माली पुत्र मुंशी
  - 2/2. जुगल माली पुत्र मुंशी
  - 2/3. गुडडी माली पुत्री मुंशी पत्नि रोशन माली निवासी बरखेडा हाल निवासी ग्राम कल्याणी तहसील व जिला करौली
  - 2/4. जय कुमारी पुत्री मुंशी पत्नि विजय माली निवासी बरखेडा हाल निवासी कल्याणी तहसील व जिला करौली
  - 2/5. सीमा माली पुत्री मुंशी पत्नि हनुमान निवासी बरखेडा हाल निवासी मोतीपाल के बाग के पीछे करौली
  - 2/6. सरोज पुत्री मुंशी पत्नि मुकेश जाति माली निवासी बरखेडा हाल नौगांव चौकी गंगापुर सिटी
3. गोपाली पुत्री परसादी माली निवासी बरखेडा के पास करौली
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

रेसपो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 423/02 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.02.20 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री नवल किशोर शर्मा

अभिभाषक रेसपो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 15.12.2025

**निर्णय**

प्रस्तुत अपील अपीला0 की आरं से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.2.20 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेसपो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 6472 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा कस्बा करौली मे स्थित है। जिसमे वादी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 1 व 2 का 2/3 हक हिस्सा खातेदारी है। प्रतिवादी न0 1 व 2 के दिल मे बदनियती आ गई और आराजी को बिना बंटवारा कराये ही रहन बय करने पर आमदा है। दिनांक 24.11.02 को प्रतिवादी न0 1 व 2 ने वादी से ऐलानिया विक्रय करने को कहा । वादी ने मना किया तो झगडा फिसाद पर आमदा हो गये। इसलिए वाद करना आवश्यक हुआ। इसलिए न्यायहित मे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। वादी/रेसपो0 प्रतिवादी


राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर



न0 1 व 2 को एक साथ काशत करना असंभव है इसलिए वादी अपने 1/3 हिस्से का बंटवारा कराने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा न0 6472 की बीघा 8 विस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 9 तहसील करौली का बंटवारा किया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा सेपरेट किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी को रहन बय ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य दीगर से करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी प्राथमिक डिकी किये जाने एवं अपीलांट/प्रतिवादी न0 2 का काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी न0 2 कल्याण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी परवर्स,आर्वीट्रेटरी, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के विनिश्चय पक्षकारान की और से प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री के विपरीत करके विधि एवं तथ्यो की गंभीर भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 न0 1 द्वारा विवादित आराजी को संयुक्त रूप से काशत करने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा रेस्पो0 संख्या 2 ने जबाब दावा मे विवादित आराजी पर पृथक पृथक कब्जा काशत होना स्वीकार किया है जिसका खण्डन वादी रेस्पो0 न0 1 द्वारा नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पक्षकारान के संयुक्त कब्जे काशत की नहीं है और पक्षकारान पृथक पृथक रूप से काबिज काशत है। इस कारण निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने वादी रेस्पो0 के वाद पत्र की विस्तृत जबाबदेही मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत की है जिसका जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम मे अपीलांट द्वारा विवादित आराजी का पूर्व खातेदारान के बीच बाहमी बंटवारा होने व अपने हिस्से की आराजी पर पृथक एवं स्वतंत्र रूप से काबिज काशत होने के तथा अपने हिस्से की आराजी पर अपने द्वारा पक्की दुकान एवं पाटोरपोश घर का निर्माण करने एवं कुआ खुदवाने की तथा अपनी दुकान मे आटा चक्की लगी होने एवं स्वयं की बगीची लगी होने के स्पष्ट अभिवयन किये गये है। और इन अभिवचनो के सर्मथन मे दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की है। जिस काउन्टर क्लेम का जबाब भी वादी रेस्पो0 द्वारा दिया गया है किन्तु वादी रेस्पो0 ने अपीलांट के उक्त अभिवचनो की सरसरी तौर पर ही इंकारी की है जो विधि अनुसार स्वीकारोक्ति की श्रेणी मे आता है। वादी रेस्पो0 ने अपने जबाब मे यह नहीं बताया है कि दुकान एवं घन व आटा चक्की एवं कुआ तथा बगीची उसने संयुक्त रूप से बनाई है और अपीलांट की चक्की होने से इंकार नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काशत की नहीं है। सत्यता यह है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विवादित जमीन खरीदने से पूर्व से ही अपीलांट की अपने हिस्से की भूमि पर सम्पूर्ण निर्माण मौजूद था और जमीन खरीदते समय रेस्पो0 को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी थी कि सहखातेदारान मे पूर्व मे ही बहामी बंटवारा हो रहा है। इस कारण तनकी संख्या 1 पर अधिनस्थ न्यायालय का विनिश्चय विधि विरुद्ध है और अपास्त

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

होने योग्य है। विवादित आराजी के सहखातेदारान के पास विवादित भूमि के अतिरिक्त और भी जमीने थी जिन सबका बाहमी बंटवारा होने के बाद ही सहखातेदारान ने जमीन बेची है। रेस्प0 संख्या 1 भूमाफिया है और जमीन खरीद फरोख्त कर बिना कर्नवर्जन कराये प्लाटिंग करता है। विवादित जमीन भी उसने इसी उद्देश्य से खरीद की है और इसी कारण सडक के हिस्सो पर काब्जिज होना चाहता है जबकि अपीलांट गरीब काश्तकार है। इस कारण अपील स्वीकार होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्प0 संख्या 2 व 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दी गई साक्ष्य के विरुद्ध अपीलांट को प्रतिपरीक्षा की अनुमति नही देकर विधि की गंभीर भूल की है। तथा अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि प्रतिवादी संख्या 2 एवं वादी रेस्प0 संख्या 1 के बीच दुरभी संधि रही है और प्रतिवादी न0 2 ने अपने अभिवचनो के विपरीत साक्ष्य दी है तथा प्रतिवादी न0 2 ने अपीलांट की चक्की, दुकान व कुआ तथा बगीची के निर्माण से इंकार नही किया है। इस कारण तनकी संख्या 1 पर अधिनस्थ न्यायालय का विनिश्चय अवैध है और अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का विनिश्चय अपीलांट के विरुद्ध करके विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध तरीके से यह निर्णित किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विधि अनुसार साबित नही किये गये जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज विधि अनुसार साबित किये गये हैं और उक्त दस्तावेजात को रेस्प0 संख्या 1 व रेस्प0 संख्या 2 व 3 के पिता परसार्दी द्वारा अस्वीकार भी नही किया गया है तथा उक्त दस्तावेजात पर अपीलांट से कोई जिरह भी नही की गई है जिससे स्पष्ट है कि उक्त सभी दस्तावेज विधि अनुसार स्वीकृत वास्तविक है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजो को इस आधार पर नजर अंदाज किया है कि उक्त दस्तावेज मे कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। अधिनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष पूर्णतः विधि विरुद्ध है। क्योंकि किसी भी पक्षकार ने ऐसी आपत्ति नही की है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विवादित आराजी के न होकर किसी दीगर आराजी के हो और उक्त दस्तावेजो से पूर्णतः स्पष्ट भी है कि उक्त सभी दस्तावेज विवादित आराजी के ही है जिन दस्तावेजो से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि विवादित आराजी वादी रेस्प0 संख्या 1 व अपीलांट द्वारा खरीदने से पूर्व ही खातेदारो के द्वारा विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा हो चुका था और अपीलांट एवं रेस्प0 संख्या 1 ने विवादित आराजी पर पृथक पृथक कब्जा प्राप्त किया है। इस कारण तनकी संख्या 2 पर अधिनस्थ न्यायालय का विनिश्चय विधि विरुद्ध है। और अपास्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 2.3.20 को दी गई। कोराना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन हो जाने के कारण तथा अपीलांट के वृद्ध होने से कोराना संक्रमण से पीडित हो जाने के कारण अपील समय पर पेश नही की जा सकी। इस प्रकार अपील पेश करने मे हुए बिलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्प0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि आराजी खसरा न0 6472 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा स्थित कस्बा करौली संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। जिसमे वादी/रेस्प0 संख्या 1 व प्रतिवादी न0 1 व 2 का समान 1/3, 1/3 हिस्सा है। जो जमाबंदी सम्वत प्रदर्श 1 से

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

स्पष्ट है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि भूमि का बहामी बंटवारा हो चुका है। जबकि सत्यता यह है कि यदि बंटवार हो जाता तो वादी/रेस्पों संख्या 1 को वाद पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवाधक संख्या 1 कायम किया जाकर उसको सिद्ध करने का भार वादी/रेस्पों संख्या 1 पर रखा था जिसे वादी/रेस्पों संख्या 1 द्वारा विधिवत रूप से साबित किया है। जिसके समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2056-59 पेश की है। जिसमें भूमि संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड होना सिद्ध है। जहाँ तक कब्जे का संबंध है तो वादी द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी पर अपने हिस्से पर कब्जा होना माना है जिसका खण्डन करने से प्रतिवादी न० 1 परसादी ने इंकार किया है तथा जबाब में भी बाहमी बंटवारा होने को इंकार किया है। अपीलाट द्वारा बाहमी बंटवारे के संबंध में जो लिखापट्टी पेश की है उसमें वादग्रस्त आराजी का नम्बर ही नहीं है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन भी मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात का पूर्व में बाहमी बंटवारा हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात हो विधिवत साबित नहीं माना है। विवाधक संख्या 2 को सिद्ध करने का भार अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 को दिया गया था जिसे अपीलांट साबित करने में असफल रहे है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वादी/रेस्पों अपने हिस्से का सेटरेट खाता कायम कराने का अधिकारी है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजात में माना है। वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी सहमति प्रकट की गई है। जहाँ तक भूमि में हो रहे पक्के निर्माण दुकान वगैरे के संबंध में प्रश्न है तो यह स्थिति तहसीलदार करौली द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में स्पष्ट होती। अपीलांट द्वारा बंटवारा स्कीम प्रस्तुत होने से पूर्व ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग स्थगित हो गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र विधिवत रूप से विवाधक कायम किये जाकर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न० 6472 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा वादी एवं प्रतिवादी न० 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जो जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का विनिश्चय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री के विपरीत किया है। जबकि अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी/रेस्पों संख्या 1 को दिया गया था। जिसे वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 से एवं पूर्व में बाहमी बंटवारा होने के कथन को प्रतिवादी संख्या 1 परसादी द्वारा इंकार किया है। इस प्रकार तनकी संख्या को विधिवत रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन किये जाने के उपरान्त ही निर्णित की है। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार अपीलांट/प्रतिवादी न० 2 पर था जिसे अपीलांट/प्रतिवादी न० 2 सिद्ध करने में असफल रहने के कारण तनकी संख्या 2 विरुद्ध प्रतिवादी/अपीलांट निर्णित की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

है। जहाँ तक वादग्रस्त आराजीयात मे निर्माण का प्रश्न है कि निर्मित दुकान,कुआ व चक्की आदि किसके हिस्से मे निर्मित है एवं कब से निर्मित है तो यह स्थिति बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर ही स्पष्ट हो पाती। अपीलांट द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त होने से पूर्व ही अपील दायर की गई है। जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार करौली को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तलब की गई है। जिसमे किसी प्रकार का कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 423/02 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.02.2020 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(लक्ष्मी कांत बालोत)  
राजस्थ अपील प्राधिकारी  
सर्वाइ माधोपुर

डिगरी बसीगे अपील  
(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

( Civil Procedure code, Appendix G )

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

कल्याण पुत्र रतन जाति कहार निवासी बरखेडा पुल करौली तहसील व जिला करौली  
अपीलांत

बनाम

1. विष्णु चंद पुत्र कल्याण प्रसाद जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली
2. मुंशी पुत्र परसादी जाति माली निवासी बरखेडा के पास करौली तहसील व जिला करौली(मृतक)
  - 2/1. महेश माली पुत्र मुंशी
  - 2/2. जुगल माली पुत्र मुंशी
  - 2/3. गुडडी माली पुत्री मुंशी पत्नि रोशन माली निवासी बरखेडा हाल निवासी ग्राम कल्याणी तहसील व जिला करौली
  - 2/4. जय कुमारी पुत्री मुंशी पत्नि विजय माली निवासी बरखेडा हाल निवासी कल्याणी तहसील व जिला करौली
  - 2/5. सीमा माली पुत्री मुंशी पत्नि हनुमान निवासी बरखेडा हाल निवासी मोतीपाल के बाग के पीछे करौली
  - 2/6. सरोज पुत्री मुंशी पत्नि मुकेश जाति माली निवासी बरखेडा हाल नौगांव चौकी गंगापुर सिटी
3. गोपाली पुत्री परसादी माली निवासी बरखेडा के पास करौली
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 50/2020 निर्णय व प्राथमिक डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली दिनांक 17.2.20 दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट । यह अपील संख्या 50/20 व तारीख 15.12.25 रुबरू हमारे व हाजिरी श्री नवल किशोर शर्मा अभिभाषक मिन जानिब अपीलांत तथा रेस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल । उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति समाप्त के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांत खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 423/02 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 17.2.20 को यथावत रखा जाता है।

बसब्त मुहर अदालत आज तारीख 15.12.25 को जारी किया।



राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांत	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	----	----	स्टाम्प वकालतनामा	----	----
स्टाम्प वकालतनामा	----	----	स्टाम्प अर्जी	----	----
इजराय हुक्मनामा	----	----	इजराय हुक्मनामा	----	----
वकील फीस बाबत	----	----	महन्ताना वकील	----	----